झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी हैसियत नहीं होती।
– अज्ञात

विचार-प्रवाह

देहरादून मंगलवार 12 मई 2020

पेज थ्री
www.page3news.in

महामारी चिकित्सकीय समस्या नहीं

क्या यह महामारी अधिनायकवाद की ओर ले जाएगी, इसके जवाब में वह कहते हैं कि महामारी कई बार अधिनायकवाद लाती है तो कई बार इसका उलटा भी होता है। जैसे हैती में येलो फीवर के बाद स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया।

मनमोहन सिंह।

कोई भी महामारी केवल चिकित्सकीय समस्या नहीं होती। वह सभ्यता को एक्सपोज करने वाली घटना भी होती है। आज दुनिया भर के गहरे चिंतक–विचारक कोरोना वायरस की व्याख्या इसी रूप में कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह इसने वैश्विक उपलब्धियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रफेसर एमेरिटस और पिछले साल प्रकाशित किताब 'एपिडेमिक्स एंड सोसाइटी रू फ्रॉम दि ब्लैक डेथ टु दि प्रेजेंट' के लेखक फ्रैंक स्नोडेन मानते हैं कि हरेक महामारी अपने आप में विशिष्ट होती है और यह समाज के बारे में बहुत कुछ बता जाती है।

कोविड–19 को भूमंडलीकृत विश्व की पहली महामारी बताने वाले स्नोडेन ने पिछले दिनों एक समाचारपत्र को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अपनी किताब के लिए शोध करने के दौरान ही कोई महामारी फैलने का आभास हो गया था, लेकिन यह इतनी जल्दी फैलेगी, यह नहीं सोचा था। उनका कहना है कि जिस तरह की दुनिया हमने बना रखी है उसमें रोगाणुओं का विस्फोट कभी भी हो सकता था।

19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने मुंह और मलद्वार से होने वाले संक्रमण के हालात पैदा किए, जिस कारण हैजा और टायफायड जैसी बीमारियां फैलीं। लेकिन मौजूदा सदी में बढ़ती जनसंख्या, फैलते महानगरों और पर्यावरण की कीमत पर हो रहे लोलुपतापूर्ण विकास ने कोरोना के लिए जमीन तैयार की है। जैव विविधता और वन्य जीवों के आवास नष्ट करके हम उनकी बीमारियों के भंडार तक पहुंच गए। उनके दायरे में इंसानी घुसपैठ ने ही हाल के दिनों में सार्स, एवियन फ्लू, इबोला और मर्स जैसी बीमारियां पैदा की हैं।

आज चौबीसों घंटे हवाई सेवा जारी रहती है। नतीजतन जो बीमारी सुबह जकार्ता में होती है वह शाम तक लॉस एंजिलिस पहुंच जाती है। क्या यह महामारी अधिनायकवाद की ओर ले जाएगी, इसके जवाब में वह कहते हैं कि महामारी कई बार अधिनायकवाद लाती है तो कई बार इसका उलटा भी होता है। जैसे हैती में येलो फीवर के बाद स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया। नोबेल विजेता, तुर्की के प्रसिद्ध उपन्यासकार ओरहान पामुक का कहना है कि महामारियों में अद्भुत समानता रही है। चाहे वह कॉलरा हो या प्लेग या कोरोना वायरस, सबमें बीमारी के लिए जिम्मेदार सूक्ष्मजीवी कमोबेश एक जैसे थे, और सरकारों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं भी।

स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों ने शुरू में इनकी मौजूदगी से ही इनकार किया, फिर इसका ठीकरा अपने मनचाहे शत्रु पर फोड़ने का प्रयास किया। अमेरिकी विचारक नोम चॉम्स्की कोरोना को गंभीर समस्या मानते हैं, पर उनका कहना है कि जैसा राजनीतिक नेतृत्व अभी दुनिया को हासिल है, उसे देखते हुए एटमी युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग और जर्जर लोकतंत्र का खतरा भी वास्तविक है। इतिहासकार और दार्शनिक युवाल नोआ हरारी के अनुसार कोरोना एक बड़ी महामारी जरूर है लेकिन इससे लड़ा जा सकता है। इसके लिए दुनिया को साथ आना होगा, पर राजनेताओं को आरोप–प्रत्यारोप से ही फुर्सत नहीं है।

स्वार्थरहित स्नेह

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। इस पूरे प्रकरण में उन्हें श्रीराम की सदाशयता पर, उनकी अपने प्रति निष्ठा और स्वार्थरहित स्नेह पर कोई संदेह नहीं होने पर भी कहीं ना कहीं उनका चित्त द्वयात्मकता का प्रक्षेपण अनुभूत करता है। ग्लानिभाव की अधिकता मनुष्य को निर्मल कर देती है, तथापि वो समग्रता में निर्मल हैं तो इससे अधिक की गुंजाइश कहां! ष्भाव भरत साष होने की आज भी दुहाई दी जाती है किंतु तत्कालीन परिस्थिति भरत के लिए अग्नि परीक्षा से भी ज्यादा दुःसाध्य है।

मानसिक मंथन का अद्भुत दृश्य उपस्थित है और भरत की जड़ता सहसा किसी निश्चय पर पहुंच जाती है, जहां श्रीराम के समस्त आग्रहों के बावजूद भी कर्तव्यवहन के रूप में राज्याधिकार को धारण कर सन्यस्त भाव से उसका संचालन करने का निर्णय शामिल होता है और पश्चात जो घटित होता है, उससे समस्त संसार वाकिफ है।

संपादकीय

चुनौतियां कम नहीं

बिहार में 21 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रहने के बाद वहां से निकलेंगे तो उन्हें राज्य तक आने में हुए तमाम खर्चे दिए जाएंगे और उसके अलावा 500 रुपये और दिए जाएंगे। हर व्यक्ति को दी जाने वाली यह राशि न्यूनतम एक हजार होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने जान–बूझकर कोई घोषणा इस संबंध में पहले नहीं की, क्योंकि हमारी सरकार का विश्वास बोलने में नहीं बल्कि काम करने में है। हमारे सुझाव पर बिहार के रहने वाले प्रवासी जो बाहर फंसे हुए हैं, चाहे छात्र हों या फिर मजदूर हों, उन्हें रेलगाड़ी के माध्यम से वापस लाया जा रहा है। बहरहाल, इस संकट के गुजर जाने के बाद भी चुनौतियां कम नहीं होने जा रहीं। राज्य सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे, जिनसे बिहार की तस्वीर बदले और लोगों के सामने पलायन की नौबत ही न आए। लॉकडाउन के बाद जब मजदूरों के हालात देश के सामने आए तो चारों ओर से कहा जाने लगा कि प्रवासी मजदूर जहां कहीं फंसे हुए हैं उनको समुचित स्वास्थ्य देखभाल के बीच घर वापस भेजने का प्रबंध किया जाना चाहिए। वे जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस मामले में शुरू में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रवैया बेहद ढीला रहा। जब विभिन्न राज्यों ने अपने मजदूरों को वापस बुलाने का फैसला किया तब भी नीतीश बहुत मुस्तैद नहीं दिखे।

अब जबकि और राज्यों के मजदूर घर पहुंचने लगे हैं तब जाकर उन्होंने इस बारे में कुछ बोलना जरूरी समझा है। अब बिहार सरकार ने घोषणा की है कि बाहर से आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों का सारा खर्च राज्य सरकार देगी।

राज्य सरकारों की बेरुखी इसके लिए सीधे जिम्मेदार रही है। रोजगार के अवसरों का अभाव होने के कारण प्रदेश के नौजवान नौकरियों की तलाश में पलायन को मजबूर हैं।

नेतृत्व की बेरुखी

यशवंत सिन्हा।

कोरोना वायरस के संकट के साथ प्रवासी मजदूरों की पीड़ा भी देश के सामने उभरकर आई है। इसी के साथ बिहार एक बार फिर राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय बना है क्योंकि ज्यादातर प्रवासी मजदूर और कामगार बिहार के ही हैं। उनकी दुर्दशा को देखते हुए यह सवाल सिर उठाने लगा है कि आखिर बिहार से इतने बड़े पैमाने पर पलायन अब भी क्यों जारी है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो लोगों को अपना घर छोड़ने को बाध्य कर रही हैं। सचाई यह है कि बिहार से सिर्फ श्रमिक वर्ग का ही पलायन नहीं हुआ है, बल्कि वहां का मध्यवर्ग भी शिक्षा और रोजी–रोटी के लिए अपना घर छोड़कर महानगरों का रुख कर रहा है।

राज्य सरकारों की बेरुखी इसके लिए सीधे जिम्मेदार रही है। बिहार देश के सबसे गरीब प्रदेशों में शुमार है, जहां की करीब 33 फीसदी आबादी निर्धनता रेखा के नीचे गुजर–बसर करती है। रोजगार के अवसरों का अभाव होने के कारण प्रदेश के नौजवान नौकरियों की तलाश में पलायन को मजबूर हैं। यही वजह है कि बिहार देश का दूसरा ऐसा प्रांत है, जहां से रोजी–रोटी की तलाश में सबसे अधिक लोग अन्य राज्यों का रुख करते हैं। कोरोना वायरस के कहर का असर देश में रोजगार पर पड़ने की बात सामने आने से पहले ही बिहार के 40 फीसदी युवा बेरोजगार हो चुके हैं। यह आंकड़ा पीरियड लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस पर आधारित है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी की दर बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार सरकार चुनाव जीतने के लिए सुशासन का प्रचार कर रही है मगर प्रदेश की गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए इस पर यकीन करना मुश्किल है। बिहार में 2011–12 और 2017–18 के दौरान बेरोजगारी की दर क्रमशः 2.5 फीसदी और 7.2 फीसदी रही है।

इंडियास्पेंड के विश्लेषण के अनुसार, अगर आप ज्यादा पढ़े–लिखे हैं तो बिहार में आपके लिए बेकारी की संभावना ज्यादा होती है। उद्योग और औपचारिक रोजगार के अवसर के अभाव में बिहार की आधी से अधिक युवा आबादी कृषि पर निर्भर करती है। यही कारण है कि बिहार देश के सबसे गरीब सूबों में शुमार है, जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का एक तिहाई है। प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत 1,42,719 रुपये सालाना है, जबकि बिहार में यह 47,541 रुपये है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का औसत 68,792 रुपये है जिससे बिहार काफी पीछे है।

नीति आयोग द्वारा जारी 2019–20 के एसडीजी सूचकांक के गरीबी के स्कोर कार्ड को देखें तो इससे भी ज्यादा दुखद पहलू सामने आता है। इसके अनुसार, बिहार न सिर्फ पहले से अत्यंत गरीब राज्य है बल्कि यह हर साल और गरीब होता जा रहा है। बिहार का स्कोर 2018 में जहां 45 था वहीं 2019 में फिसल कर 33 पर आ गया है। दरअसल, बिहार की तस्वीर बदलने के लिए इसकी तरक्की के लिए प्रदेश सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। खासतौर से प्रदेश की शिक्षा संबंधी बुनियादी जरूरतों की तरफ मुख्यमंत्री ने ध्यान ही नहीं दिया।

सूडोकु नवताल-5342

★★★★☆ मध्यम

5					9	6		
						1	4	
			2	8				
			8				5	2
6								7
1	4				3			
				4	1			
	2	5						
		3	7					4

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5341 का हल

3	6	5	1	8	2	7	4	9
7	9	2	3	5	4	1	8	6
4	1	8	6	7	9	5	3	2
6	5	9	2	4	8	3	7	1
8	4	7	9	3	1	6	2	5
1	2	3	5	6	7	4	9	8
2	7	6	4	9	5	8	1	3
5	8	1	7	2	3	9	6	4
9	3	4	8	1	6	2	5	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

सुशासन का राग

मोहन। बिहार में बीते 15 साल से सुशासन का राग अलाप रही सरकार के कामकाज का आलम यह है कि प्रदेश में एक लाख की आबादी पर सात कॉलेज हैं जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 28 है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सरकार विफल रही। शिक्षक और छात्र के अनुपात की बात करें तो बिहार में यह सबसे कम है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री वर्षों से शिक्षकों के खाली पदों पर अयोग्य उम्मीदवार नियुक्त करते रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर महज 55 फीसदी और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 55 फीसदी शिक्षक ही आज पेशवर तरीके से योग्य हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि शिक्षा को माफिया के हाथों सौंप दिया गया है। बिहार में न सिर्फ शिक्षा का स्तर नष्टप्राय है बल्कि पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्वास्थ्य ढांचा और सामाजिक बुनियाद भी कमजोर रही है। बिहार सरकार की नाकामी के कारण ही इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोजी–रोटी या बेहतर शिक्षा की तलाश में पलायन करना पड़ा, जो आज लॉकडाउन को लेकर पैदा हुई मुसीबत को झेल रहे हैं।